उदयपुर में आयोजित होगा राज्यस्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह

मुख्यमंत्री भजनलाल ने वरिष्ठ अधिकारियों को आमजन की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा

- जयपुर के साथ उदयपुर में भी सभी प्रमुख इमारतों, दर्शनीय स्थलों व सरकारी कार्यालयों में विशेष सजावट की जायेगी।
- पुलिस, शिक्षा, सार्वजनिक विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों को कार्यक्रम के लिये आपसी समन्वय रखने के निर्देश दिये गये।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उदयपुर में होने वाले राज्यस्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों के संबंध में उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए सभी अधिकारी अपने निर्धारित दायित्व को पूरा करते हुए आपस में समन्वय के साथ कार्य करें।

जयपुर, 7 जनवरी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि 76वें गणतंत्र दिवस का राज्यस्तरीय समारोह हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हर्षोल्लास के साथ भव्य और परंपरागत रूप से आयोजित किया जाएगा। इस बार यह समारोह झीलों की नगरी उदयपुर में आयोजित होगा। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए सभी अधिकारी अपने निर्धारित दायित्व को पूरा करते हुए आपस में समन्वय के साथ कार्य करें। शर्मा मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर राज्यस्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों के संबंध में उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस के राज्यस्तरीय आयोजन में राष्ट्रीयता की भावना को इंगित करते हुए कार्यक्रम शामिल करें। साथ ही, समारोह में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजधानी जयपुर की सभी प्रमुख इमारतों, दर्शनीय स्थलों तथा सरकारी कार्यालयों के साथ ही, उदयपुर में भी सभी प्रमुख स्थानों पर आकर्षक सजावट की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि राज्यस्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने वाले अतिथियों को निमंत्रण पत्र भेजने से लेकर उनके आवागमन, ठहरने और भोजन की उचित व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि राजभवन जयपुर तथा सहेलियों की बाड़ी उदयपुर में आयोजित होने वाले एटहोम कार्यक्रम के लिए भी सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं।

शर्मा ने निर्देश दिये कि अधिकारी, समारोह स्थल पर आगंतुकों की बैठने की व्यवस्था, पेयजल, मेडिकल टीम, सुरक्षा, बैरिकेडिंग एवं यातायात व्यवस्था सहित, सभी तैयारियां समय पर पूरी होना सुनिश्चित करें। अधिकारी, समारोह के दौरान स्कूली बच्चों के कार्यक्रम, लोक कलाकारों द्वारा प्रस्तुति, पुरस्कार वितरण कार्यक्रम आदि से संबंधित सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से किया जाना भी सुनिश्चित करें। उन्होंने पुलिस, शिक्षा, सार्वजनिक निर्माण, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों को आपसी समन्वय से कार्य करते हुए अपनी-अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को सभी स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद रखने के भी निर्देश दिए। बैठक में शासन सचिव सामान्य प्रशासन जोगा राम ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस के आयोजन की तैयारियों की रूपरेखा रखी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गणतंत्र दिवस पर आयोजित होने वाले राज्यस्तरीय समारोह के आयोजन में राज्य की विविधताओं को दर्शाती हुई झांकियों का प्रदर्शन किया जाए। साथ ही, समारोह में बैंड शो, कैमिल शो, घुड़सवारी शो जैसे कार्यक्रम भी शामिल करें, जिससे वे आमजन के लिए आकर्षण का केन्द्र बनें तथा युवाओं में देशप्रेम की भावना जाग्रत हो।

बैठक में मुख्य सचिव सुधांश पंत, पुलिस महानिदेशक यू आर साहू, अतिरिक्त मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) शिखर अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह आनंद कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव सार्वजनिक निर्माण प्रवीण गुप्ता, प्रमुख सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) आलोक गुप्ता सहित, शिक्षा, सूचना एवं जनसम्पर्क, पर्यटन, जयपुर जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। साथ ही, उदयपुर जिला प्रशासन के उच्च अधिकारी वीसी के माध्यम से जुड़े।

खदान में फंसे मजदूरों को निकालने के लिये सेना पहुंची

दीमा हसाओ, 07 जनवरी। असम के दीमा हसाओ जिले के उमरंगसो में 300 फीट गहरी कोयला खदान में सोमवार को अचानक पानी भर गया था, जिससे 9 मजदूर अंदर फंस गए। मजदूरों के फंसने की सूचना 34 घंटे पहले, सोमवार सुबह करीब 7 बजे मिली थी। अब इन मजदूरों के रेस्क्यू में सेना को लगाया गया है। असम के माइनिंग मिनिस्टर कौशिक राय घटनास्थल पर मौजूद हैं। भारतीय सेना और असम

- खदान में भरे पानी को दो मोटरों की मदद से निकाला जा रहा है।

राइफल्स के गोताखोर और मेडिकल टीम के साथ इंजीनियर्स टास्क फोर्स रैस्क्यू में शामिल हो गई हैं।

कुछ रिपोर्ट्स में 3 मजदूरों के शव दिखने की बात कही गई। पुलिस ने खदान के मालिक पुनीश नुनिसा को गिरफ्तार कर लिया है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह रैट माइनर्स की खदान है। इसमें 100 फीट तक पानी भर गया है, जिसे दो मोटरों की मदद से निकाला जा रहा है।

आसाराम बापू को 31 मार्च तक की अंतरिम जमानत मिली

सुप्रीम कोर्ट ने स्वास्थ्य कारणों से जमानत दी, पर, वे अपने अनुयायियों से मुलाकात नहीं कर पायेंगे

- आसाराम 17 दिन का पैरोल खत्म होने पर 6 दिन पहले ही जोधपुर जेल वापस आये थे।
- वे 2013 में गिरफ्तार हुये थे तथा तब से जेल में है।

नई दिल्ली,07 जनवरी। राजस्थान की जोधपुर जेल में बंद आसाराम बापू को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। कोर्ट ने आसाराम बापू को अंतरिम जमानत दी है। पिछले दिनों बीमार चल रहे आसाराम बापू को इलाज के लिए महाराष्ट्र भी ले जा गया था। बीच में सूरत की लाजपोर जेल में बंद उनके बेटे को गुजरात हाईकोर्ट ने बीमारी के चलते मिलने की अनुमति दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने स्वास्थ्य कारणों के कारण आधार पर आसाराम बापू को 31 मार्च तक अंतरिम जमानत दी है। हालांकि, इस दौरान कडी शर्तें भी लागू रहेंगी। आसाराम बापू अंतरिम जमानत की अवधि में अपने फॉलोवर्स और अनुयायियों से मुलाकात नहीं कर पाएंगे। आसाराम बापू 17 दिन की पैरोल खत्म होने के बाद छह दिन पहले ही राजस्थान की जोधपुर जेल में वापस लौटे थे।

ज्ञातव्य हैं कि आसाराम को जोधपुर पुलिस ने 31 अगस्त 2013 को बलात्कार के मामले में गिरफ्तार किया था और तब से वे जेल में हैं। एक किशोरी ने उन पर जोधपुर के पास मणई गांव में स्थित उनके आश्रम में यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की रहने वाली यह लड़की आश्रम में छात्रा थी। आसाराम बापू को इसके अलावा गांधीनगर की अदालत ने बलात्कार के मामले में सजा दी थी।

इस मामले में आसाराम को सेशन कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी। आसाराम के खिलाफ रेप का यह मामला साल 2013 में दर्ज हुआ था। पीड़िता के साथ रेप की वारदात साल 2001 से 2006 के बीच हुई थी। यह मामला अहमदाबाद के चांदखेड़ा थाने में दर्ज हुआ था। आसाराम पिछले साढ़े 11 साल से जेल में हैं। आसाराम के बेटे नारायण साईं के खिलाफ भी दुष्कर्म का केस दर्ज हुआ था। इस मामले में साईं को उम्रकैद हुई है। वह सूरत की जेल में बंद है।

डल्लेवाल की स्थिति नाज़ुक, दिन में एक घंटा बेहोश रहे

किसान मोर्चा ने केन्द्र सरकार को चेतावनी दी कि डल्लेवाल को कुछ हो गया, तो स्थिति नहीं संभलेगी

- डल्लेवाल के स्वास्थ्य पर जारी बुलेटिन के अनुसार, रात में उनका बी.पी. व पल्स बहुत नीचे गिर गया था। यदि यही हालात रहे तो कभी भी कुछ भी हो सकता है।

पटियाला, 07 जनवरी। खनौरी बॉर्डर पर 43 दिन से आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की बिगड़ती स्थिति को लेकर किसान मोर्चा के सब्र का बांध टूटने लगा है।

किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने मंगलवार को केंद्र सरकार को चेतावनी दी। कोहाड़ ने कहा कि अगर डल्लेवाल को कुछ हो गया तो केन्द्र स्थिति को संभाल नहीं पाएगा। बेहतर है कि समय रहते केन्द्र सरकार किसानों की बातों को गंभीरता से सुने और उनकी मांगों को पूरा करे।

वहीं, डल्लेवाल की हालत नाजुक बनी हुई है। मीडिया बुलेटिन जारी करते हुए डॉ. अवतार सिंह ने बताया कि डल्लेवाल बात तक नहीं कर पा रहे हैं।

ब्लड प्रेशर ऊपर-नीचे हो रहा है। मंगलवार को कमजोरी की वजह से वे करीब एक घंटा तक बेहोश रहे। डॉक्टरों ने उन्हें पानी पिलाया, तब जाकर कुछ राहत मिली। बीती रात भी उनका बीपी 77/45 और पल्स रेट 38 से भी नीचे गिर गया था। रात ढाई बजे जाकर बीपी कुछ स्थिर हुआ। उन्होंने बताया कि अगर यही हालात रहे तो उन्हें कभी भी कुछ भी हो सकता है। मंगलवार को सरकारी राजिंदरा अस्पताल के डाक्टरों की टीम भी डल्लेवाल के चेकअप के लिए बॉर्डर पहुंची।

किसान नेताओं ने कहा कि 10 जनवरी को पूरे देश में ग्रामीण स्तर पर मोदी सरकार के पुतले जलाए जाएंगे, ताकि केन्द्र सरकार को पता लग जाए कि गांवों के लोग एमएसपी गारंटी कानून के मुद्दे पर डल्लेवाल के संघर्ष के साथ खड़े हैं। 13 जनवरी को नई खेती नीति के ड्राफ्ट की कॉपियां देशभर में जलाई जाएंगी। 26 जनवरी को देशभर में ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि संघर्ष की अगली रणनीति की घोषणा दोनों मोर्चों से जल्द ही की जाएगी।

जवाब नहीं दिया ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

वित्तीय अनियमितता हुई है तो उसे इसके दोषी अफसर या सक्षम प्राधिकरण से वसूला जाएगा। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता आरपी सिंह और हरेन्द्र नील ने कहा कि शुरुआत में राज्य सरकार ने जवाब पेश करने के लिए दो सप्ताह का समय लिया था। वहीं, एक माह बीतने के बाद भी सरकार ने जवाब नहीं दिया, बल्कि अदालती आदेशों की अवमानना करते हुए ट्रेनी एसआई को फील्ड पोस्टिंग में भेजने के आदेश दे दिए।

फी ट्रेड, फ्री इन्वैस्टमैंट...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मूल्यवाल और इंटरनैट कंपनी, टैन्सैंट पर सैन्य संबंध होने का आरोप लगाया है। वर्तमान में यह सबसे बड़ी मीडिया कंपनियों में से एक है और भविष्य में उच्च स्तरों तक पहुँचने की राह पर है।

अमेरिका ने कहा है कि टैन्सैंट के चीनी रक्षा विभाग के साथ गहरे सम्बंध है तथा इस प्रकार से एक सुरक्षा के लिए खतरा हैं। यह चीज़ अमेरिकन और चीनी नैट-आधारित कम्पनियों में अलगाव पैदा कर देगी। चीन ने प्रतिद्वंदी सोशल मीडिया कम्पनियाँ विकसित कर ली हैं जो आकार और जनसम्पर्क के मामले में, अमेरिकन कम्पनियों से मुकाबला कर रही हैं।

वस्तुत: 2025 अमेरिकनों के लिये चीनियों के साथ डीलिंकिंग तथा प्रतिबंधों के सिलसिलों का वर्ष बनता जा रहा है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने सी.ए.टी.एल., जो विश्व की सबसे बड़ी विद्युत वाहन बैटरी निर्माता कम्पनी है, पर भी चीनी रक्षा गतिविधियों के साथ सम्बंध रखने का लेबल लगा दिया है।

अन्तर्राष्ट्रीय बैटरी मार्केट में सी.ए.टी.एल. की व्यापक उपस्थिति है। यह एक ऐसी कम्पनी है, जिसने इस क्षेत्र ऐसी विशिष्टताएं विकसित की हैं कि यह पूरी दुनिया को बैटरी तकनीक दे रही है।

ऐसी स्थिति में, जब से क्रॉस लिंकेज की चर्चा शुरु हुई है, अमेरिकन और चीनी मार्केट एक दूसरे की विपरीत दिशा में जा रहे हैं। बाजार बड़ी उत्सुकता के साथ इस बिन्दु पर नजर रखे हुये हैं कि अमेरिका ने इस स्थिति को कहाँ तक बिगाड़ने का निश्चय कर लिया है।

न्याय मित्र महिला ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

की ओर से मामले में जवाब पेश करने के लिए समय मांगा गया। इस पर अदालत ने सरकार को चार सप्ताह का समय देते हुए शौचालयों के वर्तमान हालातों और उनमें सुधार की कार्य योजना बताने को कहा है। दरअसल हाईकोर्ट की एकलपीठ ने 3 दिसंबर को महिलाओं के लिए टॉयलैट्स की कमी को गंभीरता से लिया था और संबंधित अफसरों से पूछा था कि क्यों ना सभी नगर निगम और बोर्ड आदि सार्वजनिक क्षेत्र, गलियों और स्कूल आदि में टॉयलैट निर्माण के लिए समग्र स्कीम बनाई जाए तथा क्यों ना संबंधित स्थानीय निकाय के आयुक्त या अतिरिक्त आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी गठित की जाए अदालत ने कहा था कि घर से बाहर निकली महिलाएं अपने लिए टॉयलेट तलाश करती हैं, लेकिन उन्हें या तो टॉयलेट नहीं मिलता या मिलता है तो उसमें पर्याप्त साफ सफाई नहीं होती। जिसके कारण महिला वापस घर पहुंचने तक यूरिन रोकती है, जो गंभीर है।

राहुल गांधी बरेली कोर्ट में पेश नहीं हुए

बरेली, 07 जनवरी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद राहुल गांधी मंगलवार को एक मामले में बरेली जिला न्यायालय में पेश नहीं हुए। उनकी ओर से कोई पक्षकार भी नहीं आया।

कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए, राहुल गांधी को 17 जनवरी को पेश होने के लिये समय दिया है, अगर राहुल गांधी पेश नहीं होते है तो कोर्ट नोटिस जारी कर सकता है।

दरसअल, बीते लोकसभा चुनाव

- जिला न्यायालय ने 17 जनवरी को पेश होने का समय दिया।

के दौरान, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर बयान दिया था। इसका हिंदूवादी संगठनों ने तीखा विरोध किया था।

अखिल भारतीय हिंदू महासभा मंडल अध्यक्ष पंकज पाठक की ओर से बरेली कोर्ट में अर्जी दी गई थी। एमपी-एमएलए कोर्ट ने उस वक्त अर्जी को खारिज कर दिया था। इसके बाद पंकज पाठक ने जिला एवं सत्र न्यायालय में अपील कर दी थी।

उत्तर प्रदेश में नये अपराधिक कानून जल्दी लागू करें

अमित शाह और योगी आदित्यनाथ ने नये कानूनों के क्रियान्वयन के लिये समीक्षा बैठक की

- केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि तीन नये अपराधिक कानून दंड-केन्द्रित नहीं बल्कि पीड़ित-केन्द्रित हैं।

नयी दिल्ली, 07 जनवरी। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के सातों कमिश्नरेट्स में इस वर्ष 31 मार्च तक नए आपराधिक कानूनों का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कहा है। शाह ने मंगलवार को यहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ राज्य में तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन पर समीक्षा बैठक की। बैठक में उत्तराखंड में पुलिस, जेल, कोर्ट, अभियोजन और फॉरेन्सिक से संबंधित विभिन्न नए प्रावधानों के कार्यान्वयन और वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक में केन्द्रीय गृह सचिव, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के महानिदेशक और राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो सहित गृह मंत्रालय और उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक में चर्चा के दौरान केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि तीन नए आपराधिक कानून दंड-केन्द्रित नहीं बल्कि पीड़ित-केन्द्रित हैं और इनका उद्देश्य त्वरित न्याय सुनिश्चित करना है। गृह मंत्री ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से फरवरी माह में नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा कर इन कानूनों को राज्य में पूरी तरह जल्द से जल्द लागू करने को कहा।

शाह ने कहा कि इस बात की नियमित और निरंतर निगरानी होनी चाहिए कि दर्ज की गई कुल जीरो प्राथमिकी में से कितनी राज्यों को स्थानांतरित की गईं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को हर 15 दिन में और मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ तीन नए कानूनों के कार्यान्वयन की प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करनी चाहिए।

दिल्ली की ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

भी जैगुआर कम्पनी से खरीदे गए। माउण्ट शावर क्रोम पॉलिश वाला है और पीतल के हैंडल हटाकर स्टेन लैस स्टीन के हैंडल लगाए गए है, सिर्फ इन्हीं पर 54 लाख रु. खर्च हुए हैं।

नाबालिग...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अदालत में आरोप पत्र पेश किया। सुनवाई के दौरान पीड़िता ने अदालत को बताया कि अभियुक्त ने उसे अमरूद देने का लालच देकर अपने कमरे में बुलाया था और उसके साथ छेड़खानी की थी।

बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा रद्द नहीं होगी

नयी दिल्ली, 07 जनवरी। उच्चतम न्यायालय ने कथित तौर पर परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र सार्वजनिक होने के आधार पर बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा (प्रारंभिक) रद्द करने की मांग वाली याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार

- सुप्रीम कोर्ट ने प्रश्न पत्र सार्वजनिक होने के कारण परीक्षा रद्द करने की याचिका खारिज कर दी।

एवं न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए याचिकाकर्ता को संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत, पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने को कहा। पीठ के समक्ष याचिकाकर्ता आनंद लीगल एड फोरम ट्रस्ट के अधिवक्ता ने दलील देते हुए कहा कि सभी ने देखा कि कैसे बिहार पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर बेरहमी से लाठीचार्ज किया था। उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं में परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र सार्वजनिक होने और कदाचार के मुद्दे पर जोर देते हुए दलील दी कि जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं।

सांसद पप्पू ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

में कई गंभीर अनियमितताएं, पारदर्शिता का अभाव और प्रशासनिक विफलताएं सामने आई हैं।

राजभवन के बाहर संवाददाताओं से बात करते हुए यादव ने कहा कि प्रशांत किशोर शिखंडी हैं, और उसकी यह मांग कि आंदोलन में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव छात्रों का नेतृत्व करें, हास्यास्पद है। किशोर ने अपनी राजनीतिक दुकान चलाने के लिए छात्रों के आंदोलन को मोहरा बनाया है। सत्याग्रह के दौरान छात्रों पर बिहार पुलिस ने तीन बार लाठी चार्ज किया। उन्होंने 12 जनवरी को महागठबंधन के सभी नेताओं से बिहार बंद में शामिल होने का भी आग्रह किया है।

राज्यपाल को ज्ञापन सौंपते समय सांसद के साथ प्रेमचंद सिंह, राजेश पप्पू, राघवेन्द्र कुशवाहा, फैजान अहमद, उपस्थित थे।

चीन अरुणाचल प्रदेश...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

इस ओर लगाने को बाध्य होना पड़ सकता है।

इसके अलावा चीन पूर्वोत्तर राज्यों के आर्थिक विकास क भारत के प्रयासों को कमजोर करना चाहता है क्योंकि इससे क्षेत्र में चीन का प्रभाव कम हो रहा है।

हाल ही में यू.टी.ए. ने अरुणाचल की बांध परियोजनाओं के विरोध में बयान जारी किया। इसने चकमा शरणार्थियों को दूसरी जगह भेजने की मांग की साथ ही कहा कि नॉन ए.पी.एस.टी. (अरुणाचल प्रदेश शिड्यूल ट्राइब) को दिए गए अनुसूचित जाति प्रमाणपत्र रद्द किए जाए। ये मांगे राज्य के आदिवासी समुदायों से संबंधित है और इनसे भारी तनाव पैदा हो सकता है।

बयान का समय महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी समय एन.एच.पी.सी. (नैशनल हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन) को सिआंग अपर मल्टीपरपज़ प्रोजैक्ट के प्रीफिजिबिटी अध्ययन में सहायता देने के लिए सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। सिआंग व अपर सिआंग जिलों के लोग इस प्रोजैक्ट का विरोध कर रहे हैं और अब इस बयान से टकराव बढ़ रहा है। इसके अलावा यू.टी.ए. की मांग गैर आदिवासी से विवाद करने वाली आदिवासी महिलाओं के बच्चों को एस.टी. प्रमाणपत्र देने से सम्बंधित है, जिससे स्थानीय लोगों की नाराजगी बढ़ रही है।

यू.टी.ए. इन संवेदनशील मुद्दों पर युवा वर्ग का समर्थन जुटाने की कोशिश में लगा है क्षेत्र के कई युवा काफी निराश है उन्हें लगता है सरकार उनकी चिंता का समाधान नहीं कर रही है।

इस निराशा की वजह से युवा वर्ग के यू.टी.ए. में शामिल होने का खतरा है। उन्हें यह लग सकता है कि यह संगठन उनकी समस्याओं का समाधान कर सकता है।

इसलिए सरकार के लिए जरुरी है कि इन चुनौतियों पर सक्रियता से काम करे।

यू.टी.ए. के स्वघोषित अध्यक्ष एंथनी डोक का विवादास्पद इतिहास है वे पूर्व में नैशनल लिबरेशन काउंसिल ऑफ टानी लैंड से जुड़े हुए थे, जिसे 2010 में राज्य पुलिस ने खत्म कर दिया था। यह संगठन लोगों से वसूली भी करता था। एंथनी भी गिरफ्तार हुआ और फिर रिहा हो गया बाद में वह आम नागरिक का जीवन बिताने लगा और इटा नगर में एक रैस्त्राँ चलाने लगा।

अब उसके यू.टी.ए. के नेता के रुप में अचानक सामने आना चिंताजनक है। सुरक्षाबलों को संदेह है कि वह म्यांमार व नागालैंड आता जाता है और बागी नागा संगठनों से उसे मदद मिल रही है।

क्या बिहार ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

है। सूत्रों का कहना है कि नीतीश कुमार द्वारा लालू यादव से मुलाकात करने पर प्रधानमंत्री मोदी सख्त नाराज है।

दिल्ली विधानसभा चुनाव 5 फरवरी को...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया था, जिसमें टूट-फूट चुके तंत्र को ठीक करने के लिये राजनैतिक छलाँग लगाई है।

जहाँ तक विपक्षी गठबंधन, "इंडिया", जिसका हिस्सा आप भी है, का संबंध है, के लिये यह चुनाव ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि विपक्षी खेमे में कांग्रेस के अलावा आप ही ऐसी इकलौती पार्टी है, जो एक से अधिक राज्य की सत्ता में है। केजरीवाल के व्यक्तिगत संबंध विपक्षी नेताओं के साथ अच्छे हैं, जबकि कांग्रेस, जो ब्लॉक का नेतृत्व कर रही है, के साथ विपक्षी नेताओं के रिश्ते उतने मधुर नहीं हैं। अगर आप दिल्ली में तीसरी बार जीतती है, तो इंडिया ब्लॉक में केजरीवाल की हैसियत बढ़ेगी तथा कांग्रेस और अधिक दबाव में आ जायेगी। इसके विपरीत, आप का नुकसान होने से कांग्रेस को थोड़ी राहत मिलेगी।

पंजाब को छोड़कर, दिल्ली उत्तरी भारत का ऐसा इकलौता राज्य है, जहाँ भाजपा ने पिछले लगभग ढ़ाई दशक से सत्ता का स्वाद नहीं चखा है। लेकिन पिछले तीन दशक के भाजपा के वोट शेयर पर नज़र डालने पर ज्ञात होता है कि पार्टी अपना संतोषजनक जनाधार बनाये हुये है।

1998 से लेकर अब तक, सत्ता से बाहर रहने के बावजूद, तब से लेकर अब तक हुये 6 विधानसभा चुनावों में भाजपा का वोट शेयर 32 प्रतिशत से नीचे नहीं रहा है।

2015 में भी, जब आप को इकतरफा जीत मिली थी तथा भाजपा केवल तीन सीटों पर सिमट गई थी, उसका वोट शेयर 32.19 प्रतिशत रहा था। पाँच साल बाद, जब इसने 8 सीटें जीतीं तथा शेष सभी सीटें आप की झोली में गई थीं, इसका वोट शेयर उछलकर 38.51 प्रतिशत पर पहुँच गया था।

वोट शेयर कायम रहने के अलावा, भाजपा को एक यही बात संबल देती आ रही है कि 2014 से लेकर अब तक, इसने दिल्ली में सभी सात सीटें जीती हैं।

1998 में सत्ता से बाहर होने के बाद, भाजपा 1998, 2003 तथा 2008 के लगातार तीनों चुनाव कांग्रेस से हारी थी तथा 2013, 2015 एवं 2020 के तीन लगातार चुनाव आप से हारी है। भाजपा के साथ एक बड़ी कमी यह रही है कि पहले कांग्रेस की शीला दीक्षित तथा 2013 से आप के केजरीवाल जैसा पार्टी का कोई लोकप्रिय चेहरा भाजपा के पास नहीं रहा।

अपने पहले दो चुनावी भाषणों में, मोदी ने अपनी सरकार का मॉडल आप की सरकार के मॉडल के विरूद्ध रखा। उनका फोकस आप सरकार के मॉडल के प्रमुख स्तम्भों की काट करने पर था। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार एक ज्यादा सक्षम कल्याणकारी व्यवस्था संचालित कर रही है। जब आप का उदय राजनैतिक क्षितिज पर हुआ था, तो इसने अपने आप को "आम आदमी" की पार्टी के रूप में प्रस्तुत किया था तथा उसी को रेखांकित करने के लिये अपना चुनाव चिन्ह "झाड़ू" रखा था। मोदी और भाजपा सीधे कच्ची बस्तियों के निवासियों तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्हें आप सरकार में बिजली-पानी मुफ्त मिल रहे हैं, वे ऑटोरिक्शा चालकों को प्रभावित करना चाह रहे हैं, जिनका स्नेह पाने के लिये आप ने बहुत मेहनत और काम किया है।

लोकसभा चुनाव में मिले झटके के बाद, भाजपा ने हरियाणा और महाराष्ट्र में धमाकेदार वापसी की सराहनीय क्षमता दर्शाई थी। वह जीत के इस सिलसिले को दिल्ली तक लाना चाहेगी, ताकि इस आधात से विपक्ष पूरी तरह पंगु होकर रह जाये।

दिल्ली में कांग्रेस का उत्थान और पतन बड़ा नाटकीय रहा है। पार्टी 1998 में दिल्ली की सत्ता में आई, जबकि कुछ ही महीने पहले, वह लोकसभा चुनावों में बुरी तरह हार गई थी। दिल्ली में भी, भाजपा ने सात में से छ: सीटें जीती थीं। कांग्रेस की ओर से इकलौती विजेता मीरा कुमार थीं, जो करोग बाग सीट से जीती थीं और तो और, दीक्षित, जो कुछ ही माह बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री बनीं, पूर्वी दिल्ली सीट पर भाजपा के लाल बिहारी तिवारी से हार गई थीं।

लेकिन, इन लोकसभा चुनावों के कुछ माह बाद हुये विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने 70 मे से 52 सीटें जीतीं तथा इसका वोट शेयर 47.7 प्रतिशत रहा तथा उस समय मुख्यमंत्री बनीं शीला दीक्षित 15 साल तक इस पद पर आसीन रहीं। उनका शासन 2013 में समाप्त हुआ, जब कांग्रेस केवल 8 सीटों पर सिमट गई तथा स्वयं दीक्षित, केजरीवाल से हार गईं।

2015 में पार्टी को और भी बड़ा धक्का लगा, क्योंकि दिल्ली में अपना खाता तक नहीं खोल सकी। इसका वोट शेयर 10 प्रतिशत से नीचे आ गया, जबकि 2008 में इसका वोट शेयर 40.31 प्रतिशत तथा 2013 में 24.55 प्रतिशत था।

और पिछले विधानसभा में पार्टी का वोट शेयर घट कर मात्र 4.26 प्रतिशत रह गया तथा इसके 66 में से 63 उम्मीदवारों की जमानतें जब्त हो गईं।

पार्टी के 15 साल के शासन का श्रेय शीला दीक्षित को भले ही मिला हो, लेकिन उस समय, दिल्ली में कांग्रेस का संगठनात्मक ढांचा काफी मजबूत था, जिसमें लगभग सभी समुदाय के लोग शामिल थे। दिल्ली में पार्टी के बहुत से दत्रप थे, जिनमें से कई तो मुख्यमंत्री पद की प्रतिस्पर्धा में भी थे।

मार्डन मीडिया, बीकानेर के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 35214/79, **जयपुर कार्यालय:** सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, **कोटा कार्यालय :** पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, **उदयपुर कार्यालय:** आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, **अजमेर कार्यालय:**-राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665, **जालोर कार्यालय :-** जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422,226423, फैक्स: 02973-226424 **हिण्डौनसिटी कार्यालय :-** जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 **चूरू कार्यालय :** एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908